3. उड़ीसा और मध्य प्रदेश में महानदी घाटी कोयला बसिन (4 परियोजनायें)।

4. मध्य प्रदेश में सोन घाटी बेसिन (2 परियोजनायें)।

5. महाराष्ट्र में वर्धा घाटी कोयला बेसिन।

6. आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी कोयला बेसिन।

7. तमिलनाड में ईस्ट कोस्ट लिग्नाइट फील्ड।

8. राजस्थान और गुजरात में वैस्ट कोस्ट लिग्नाइट फील्ड।

राष्ट्रीय खान नीति

3429. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1993 में एक राष्ट्रीय खान नीति की घोषणा की गई थी जिसके अन्तर्गत यूरेनियम, कोयला और कच्चे तेल के अतिरिक्त अन्य सभी खनिजों के खनन कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति की घोषणा के पश्चात निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संस्थानों ने सरकार के पास अपने-अपने आवेदन भेजे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस नीति की घोषणा करने से पूर्व सरकार द्वारा भारतीय खानों में खनन कार्य करने हेतु विदेशी संस्थानों को आकर्षित करने के लिये अनेक प्रतिनिधि मंडलों को विदेश भेजा गया था ;

(ङ) यदि हां, तो क्या किसी विदेशी उपक्रम द्वारा कोई पेशकश की गई हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि निजी क्षेत्र से अभी तक कोई उत्साहजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस संबंध में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने हेतु सरकार की भावी योजनायें क्या हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) राष्ट्रीय खनिज नीति 5 मार्च, 1993 को इस सदन में प्रस्तुत की गई थी, जिसके अनसार सरकारी क्षेत्र के लिये विशेष रूप से आरक्षित 13 खनिजों का खनन समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) सभी खनिजों के खनों पट्टों के आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत किये जाते हैं, और वे उन पर विचार करती है । यदि माननीय सदस्या, किसी खनिज अथवा राज्य, जिसके बारे में वे जानकारी चाहती हैं, उसका उल्लेख करें, तो उसे संबंधित राज्य सरकार से एकत्र किया जायेगा और सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते ।

3430. [*Transferred to 23rd August, 1993*]

Irregularities in Steel Development Fund Loans

3431. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are likely to lose over Rs. 2000 Crore by way of corporate tax